हमारी सरकार घोषणाएं ही नहीं करती, उसे समय से धरातल पर भी उतारती है- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने बयाना में भरतपुर संभाग के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया

जयपुर, 28 सितंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार केवल घोषणाएं ही नहीं करती, बल्कि उन्हें समयबद्ध रुप से धरातल पर उतारने का कार्य करती है। इसी क्रम में भरतपुर संभाग को विकास की नई गति देते हुए करीब 453 करोड़ रुपये के 65 बड़े विकास कार्यों का लोकार्पण और 540 करोड़ रुपये के 184 नवीन विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है। इन विकास कार्यों से क्षेत्र में आधुनिक आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बयाना व ब्रज नगर में आधुनिक स्टेडियम, थानाडांग, सूपा व महलपुर चूरा में 33 केवी सब-स्टेशन के निर्माण की घोषणा की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को भरतपुर के बयाना के बिड्यारी में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित किया। इस दौरान विधायक ऋतु बनावत ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया।

मुख्यमंत्री सोमवार को भरतपुर जिले के बयाना के बिड्यारी में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह का संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भरतपुर को 382 करोड़ रुपये से अधिक के 130 कार्यों, डीग को 358 करोड़ रुपये से अधिक के 24 कार्यों, करौली को 136 करोड़ रुपये से अधिक के 43 कार्यों, सवाई माधोपुर को 74 करोड़ रुपये से अधिक के 46 कार्यों और धौलपुर को 42 करोड़ रुपये से अधिक के 6 विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास की सौगात मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में 273 करोड़ रुपये के 14 बड़े कार्यों का लोकार्पण हुआ है तथा चुली व अनियाला में नए 33 केवी सब-स्टेशनों का भी निर्माण किया जाएगा।

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने बयाना और ब्रज नगर में आधुनिक स्टेडियम के निर्माण और थानाडांग, सूपा एवं महलपुर चूरा में 33 केवी सब-स्टेशनों के निर्माण की घोषणा की।

आईआईटी आत्महत्या के मामले में पिता ने आज़ाद मैदान पर धरना दिया

मुंबई, 28 सितंबर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की मौत के मामले में उनके पिता रवीन्द्र वाकोडे ने सोमवार को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। परिवार ने मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और साहिल को न्याय दिलाने की मांग की है। परिवार का आरोप है कि साहिल को संस्थान में कथित तौर पर जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा था।

रवीन्द्र वाकोडे ने कहा कि वे अपने बेटे को न्याय मिलने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रखेंगे। रवीन्द्र वाकोड़े के वकील निखिल कांबले ने बताया कि वाकोडे परिवार आजाद मैदान में भूख हड़ताल कर रहा है और एफआईआर में नामजद लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है।

जस्टिस विक्रम नाथ भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे

वे अगले साल फरवरी में पद संभालेंगे, जब वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत रिटायर हो जाएंगे

■ सितम्बर 1962 में जन्मे जस्टिस विक्रम नाम 2004 में इलाहाबाद में एडीशनल जज तथा 2006 में परमानैंट जज बने थे। अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होने से पहले वे गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे।

नई दिल्ली, 28 सितंबर। जस्टिस विक्रम नाथ भारत के अगले चीफ जस्टिस होंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री पूरी करने के चार दशक बाद, जस्टिस नाथ अगले साल फरवरी में देश के अगले सीजेआई की जिम्मेदारी संभालेंगे, क्योंकि वर्तमान 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत अगले साल फरवरी में रिटायर हो रहे हैं। सीजेआई सूर्यकांत का कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक है।

जस्टिस विक्रम नाथ मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के रहने वाले हैं। उनका जन्म 24 सितंबर, 1962 में हुआ था। जस्टिस नाथ ने 1983 में साइंस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया था। उन्होंने 1986 में लखनऊ विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की थी और इसके बाद 1987 में यूपी बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया।

2004 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनने से पहले, जस्टिस विक्रम नाथ ने वहां 17 साल से ज्यादा समय तक प्रैक्टिस की। 2006 में वे परमानेंट जज बने। अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होने से पहले, उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम किया। 15 अप्रैल 2022 को एक समारोह में बोलते हुए उन्होंने शिया कॉलेज में अपने स्टूडेंट लाइफ के अनुभव शेयर किए थे। उस समय उन्होंने कहा कि कॉलेज ने मेरी सफलता में अभूतपूर्व योगदान दिया। अगर शिया कॉलेज न होता, तो मैं कुछ भी नहीं होता।

एआई की दुविधा अब केवल काल्पनिक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उपयोग करना चाहती हैं, जबकि टैक्नॉलजी कंपनियाँ अधिक उन्नत सिस्टम बनाने की होड़ में लगी हैं। वही तकनीक, जो अभूतपूर्व उत्पादकता का वादा करती है, आर्थिक और तकनीकी शक्ति को कुछ बड़ी कंपनियों के हाथों में केन्द्रित भी कर सकती है।

क्या इन सिस्टमों को बनाने वाली कंपनियों पर खुद को नियंत्रित करने के लिए भरोसा किया जा सकता है? जिम्मेदार इनोवेशन के बारे में कॉर्पोरेट आश्वासन स्वतंत्र निगरानी का विकल्प नहीं हो सकते। दूसरी ओर, बहुत ज्यादा सख्त नियम निवेश को हतोत्साहित कर सकते हैं और शोध की गति को धीमा कर सकते हैं।

एआई से जुड़े इस मुद्दे का भारत पर खासा असर पड़ सकता है। देश एक वैश्विक एआई पारवरहाउस के रुप में उभरना चाहता है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि यह तकनीक देश की विकास संबंधी प्राथमिकताओं को पूरा करे। एआई से स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा और सरकारी प्रशासन में सुधार हो सकता है। लेकिन पर्याप्त सुरक्षा उपाय न होने पर नागरिकों का डेटा गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, नागरिकों को धोखाधड़ी और भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है, जबकि ऑटोमेशन रोजगार को प्रभावित कर सकता है।

भारत को ऐसे नियामक ढाँचे की जरूरत है, जो नागरिकों की सुरक्षा करे, लेकिन इनोवेशन के रास्ते में अनावश्यक रुकावटें न डाले। पारदर्शिता, स्वतंत्र सुरक्षा आकलन, जिम्मेदारी तय करने के स्पष्ट नियम और गंभीर घटनाओं की अनिवार्य रिपोर्टिंग इसके स्पष्ट आधार होने चाहिए। इसका अंतरराष्ट्रीय पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक देश में विकसित किए गए एआई सिस्टम दुनिया भर के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। सुरक्षा, सिक्योरिटी और जवाबदेही के लिए आम सिद्धांत तय करने के लिए सरकारों के बीच सहयोग जरूरी है।

अंततः सवाल यह नहीं है कि एआई को नियंत्रित किया जाना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि रैगुलेशन को तकनीकी बदलाव की गति के साथ तालमेल बिठाकर कैसे रखा जाए। न तो कंपनियों को बिना रोकटोक के पूरी शक्ति देना और न ही जरूरत से ज्यादा सरकारी नियंत्रण कोई स्थायी समाधान है। एआई गवर्नेंस की असली परीक्षा यह होगी कि क्या समाज इनोवेशन के लाभों को बनाए रखते हुए यह सुनिश्चित कर सकता है कि भविष्य को आकार देने की शक्ति उन लोगों के प्रति जवाबदेह बनी रहे, जिन्हें उसके परिणामों के साथ जीना होगा।

मेक इन इंडिया को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ये उद्योग प्रतिस्पर्धी बने रहेंगे। लंबी अवधि की परीक्षा यह है कि क्या कंपनियां सब्सिडी पर बहुत अधिक निर्भर हुए बिना अपनी प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और एक्सपोर्ट को बनाए रख सकती हैं।

निवेश के आंकड़ों को भी सावधानी से समझने की जरूरत है। 2014-15 से 2025-26 के बीच कुल 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (फॉरेन डायरैक्ट इन्वैस्टमैंट - एफ.डी.आई.) यह दिखाता है कि भारत दुनिया के निवेशकों के लिए आकर्षक है, लेकिन सारा एफ.डी.आई. मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में नहीं जाता। इसी तरह, पी.एल.आई. से जुड़े निवेश और उत्पादन के आंकड़े औद्योगिक विस्तार को तो दिखाते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि देश के अंदर वास्तव में कितना मूल्य जोड़ा गया है और इस विस्तार का लाभ कितने व्यापक क्षेत्रों तक पहुंचा है।

रोजगार भी एक महत्वपूर्ण पैमाना है। अगर मैन्युफैक्चरिंग को आर्थिक विकास का व्यापक आधार बनना है, तो उसे कहीं अधिक लोगों को रोजगार देना होगा। सैमीकंडक्टर और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे ज्यादा पूँजी वाले उद्योगों के साथ-साथ, टैक्स्टाइल गारमैंट, जूते और फूड प्रोसैसिंग जैसे ज्यादा श्रम वाले क्षेत्रों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। औद्योगिक सप्लाई चेन की रीढ़ माने जाने वाले छोटे और मध्यम उद्योगों को भी क्रेडिट, टैक्नॉलजी और एक्स्पोर्ट मार्केट तक बेहतर पहुँच की ज़रूरत है।

इसलिए भारत की मैन्युफैक्चरिंग की महत्वाकांक्षाओं के लिए फोकस में अब बदलाव की जरूरत है। अगले चरण में केवल ज्यादा सामान बनाने पर ही नहीं, बल्कि उन्हें डिजाइन करने, उनके पुर्जे विकसित करने, टैक्नॉलजी पर अपना नियंत्रण रखने और ग्लोबल स्तर पर मुकाबला करने वाले घरेलू सप्लायर तैयार करने पर जोर होना चाहिए। मजबूत रिसर्च क्षमता, भरोसेमंद इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशल कर्मचारी और ग्लोबल वैल्यू चेन में गहरी भागीदारी बहुत जरूरी है।

मेक इन इंडिया ने एक अहम नींव रखी है। लेकिन इस पहल की असली कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या यह नींव ऐसी मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था बनाती है, जो देश में ज्यादा वैल्यू पैदा करे, बड़े स्तर पर रोजगार दे और केवल सरकारी प्रोत्साहनों के भरोसे नहीं, बल्कि प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन के दम पर ग्लोबल स्तर पर मुकाबला करे।

चुनाव आयोग तीन माह में तृणमूण के चुनाव चिन्ह पर फैसला करे- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 28 सितंबर। उच्चतम न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के दोनों धड़ों के लिए चुनाव चिन्ह विवाद को निपटाने के लिए समय-सीमा तय कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बैंच ने सोमवार को कहा कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के लिए चार हफ्ते और उसके बाद फैसला करने के लिए तीन महीने का समय मुकर्रर किया है।

हालांकि, आयोग के वकील ने इस पर फैसले के लिए छह महीने का समय दिए जाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने उनके इस अनुरोध को ठुकरा दिया। इसके साथ ही, कोर्ट ने कहा कि अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो आप हमारे पास आ सकते हैं। इससे पहले 24 सितंबर को सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि निर्वाचन आयोग इस मामले पर फैसला करने में देरी कर रहा है। उन्होंने सुझाव दिया था कि इस मामले पर निर्वाचन आयोग को रोजाना सुनवाई करनी चाहिए। ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के दो विरोधी गुटों के बीच विवाद के चलते पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया गया था।

उत्तराखंड में आठ हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे

अभियान में 38 लोग बचाये गये, अभी 136 ट्रैकर्स विभिन्न स्थानों पर फंसे हैं

देहरादून, 28 सितंबर। उत्तरकाशी के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में खराब मौसम के बीच फंसे ट्रेकर्स, पर्वतारोहियों और पोर्टर्स की सुरक्षित निकासी के लिए सोमवार को युद्धस्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। आठ हेलीकॉप्टरों की मदद से ऑडेन कोल क्षेत्र के सभी 29 और कालिंदी पास क्षेत्र के नौ ट्रेकर्स समेत, अब तक 38 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। शेष लोगों की निकासी के लिए अभियान जारी है।

■ अधिकारियों के अनुसार, ऑडेन कोल क्षेत्र में फंसे सभी 29 ट्रैकर्स को सोमवार की सुबह हेलीकॉप्टर से निकाला गया। कालिंदी पास क्षेत्र से 9 ट्रैकर्स को हर्षिल हेलीपैड पहुंचाया गया।

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 10 ट्रेकिंग दलों के 136 ट्रेकर्स विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए थे। उनकी निकासी के लिए सोमवार सुबह छह बजे से आठ हेलीकॉप्टरों के जरिए अभियान शुरू किया गया। मौसम और हेलीकॉप्टर संचालन की परिस्थितियों के अनुसार रेस्क्यू रणनीति में लगातार बदलाव किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि ऑडेन कोल क्षेत्र में फंसे सभी 29 ट्रेकर्स को सोमवार सुबह ही हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाल लिया गया।

उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य जांच के बाद उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। वहीं, कालिंदी पास क्षेत्र से नौ ट्रेकर्स को हर्षिल हेलीपैड पहुंचाया गया, जहां स्वास्थ्य परीक्षण के बाद सभी की स्थिति सामान्य पाई गई।

चुनाव आयोग के मुद्दे पर खड़गे ने सीडब्लूसी की आज बैठक बुलाई

नई दिल्ली, 28 सितंबर। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर जारी विवाद के बीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक बुलाई है। बैठक में चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के साथ पार्टी की आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर गंभीरता से संघर्ष करेगी और बैठक में सीडब्ल्यूसी के सभी सदस्य अपने सुझाव देंगे। यह मामला केवल किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रही है और सीडब्ल्यूसी की बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि आयोग के कामकाज को लेकर उसके अपने लोगों की ओर से भी सवाल उठाए गए हैं।

'जीएसटी अधिकारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बताया कि सेंट्रल गुड्स एण्ड सर्विसेज़ टैक्स (सीजीएसटी) 2017, में केवल "गुड्स" (चल संपत्तियां या वस्तुओं) को परिभाषित किया गया है और इस कानून में विशेष रूप से "मनी" (नकदी) के विषय में कोई भी नियम या कायदा नहीं बनाया गया है। सिद्धार्थ रांका का कहना यह अधिनियम केवल चल संपत्ति व वस्तुओं और सेवाओं की खरीद- फरोख्त पर टैक्स से संबंधित है। इस नियम में "मनी", यानी नकदी को कहीं परिभाषित भी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि गैरकानूनी तरीके से इस नकदी को जब्त करने की वजह से याचिकाकर्ताओं को न केवल ब्याज, बल्कि मुआवजा भी मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961, की धारा 132 में 'तलाशी और अधिग्रहण (ज़ब्ती)' के संबंध में नियम लिखे गये है। उन्होंने बताया कि इस धारा में भी स्पष्ट लिखा है कि नकदी, सोना व आभूषण को 'वस्तु' की तरह परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये एक ही श्रेणी में नहीं आते है। अदालत ने कई हाईकोर्ट के निर्णयों को देखा और यह निष्कर्ष निकाला कि सीजीएसटी कानून की व्याख्या किसी भी दृष्टिकोण से की जाए, चाहे शब्दशः तरीके से, या सुनहरे नियम को लगाते हुए; जिससे नियम को लागू करने में विसंगतियों व असंगतियों को दूर रखा जा सके, या शरारत का नियम लागू करके कानून को पढ़ा जाये, ताकि कानून की भाषा अस्पष्ट न रहे, तब भी अदालत जीएसटी अधिकारियों को किसी भी सूरत में यह अधिकार नहीं दे सकती कि उन्हें छापे के दौरान नकदी जब्त करने का अधिकार है। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में पक्षकार जयपुर जोन के जीएसटी विभाग के एडिशनल डायरेक्टर, वरिष्ठ इटेलिजेंस ऑफिसर, उपायुक्त, राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के अन्य अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं की जब्त की गई नकदी वापस लौटाने के आदेश दिये।

यहां उल्लेखनीय है कि कई मामलों में नकदी जब्त करने की कार्रवाई 2023 और 2024 में की गई थी और राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष कई अन्य हाईकोर्ट के निर्णय पेश किये गये थे, जिसमें समानांतर मामलों में अदालत में जीएसटी अधिकारियों को न केवल जब्त की गई नकदी लौटाने के आदेश दिये थे, बल्कि मुआवजा व ब्याज भी देने को कहा था। परंतु हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस गुहार पर कोई आदेश नहीं दिये।

कांग्रेस ने सपा के समक्ष ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

श्रेणियों में बांटा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इसका उद्देश्य बातचीत शुरू होने से पहले संभावित उम्मीदवारों और संगठन की ताकत की पहचान करना है, ताकि गठबंधन होने की स्थिति में पार्टी के पास उम्मीदवारों की कमी न हो।

पार्टी ने 150 सीटों को अपनी पहली श्रेणी में रखा है और उम्मीद है कि बातचीत के दौरान वह इन सीटों की मांग करेगी। कांग्रेस नेताओं ने संकेत दिया है कि वे नहीं चाहते कि सीटों की अंतिम संख्या 100 से कम हो।

कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए भी काम कर रही है। पार्टी खास तौर पर दलित और ब्राह्मण मतदाताओं पर ध्यान दे रही है और अति पिछड़े समुदायों के बीच भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

जहाँ पार्टी का फोकस ब्राह्मण और दलित मतदाताओं पर है, वहीं, वह मुस्लिम नेताओं को भी अपने साथ जोड़ रही है। इस प्रयास में कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी को प्रमुख भूमिका दी गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रमुख मुस्लिम नेताओं में सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद भी शामिल हैं।

अखिलेश यादव ने हाल ही में रायबरेली से पार्टी की पीडीए (पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक) रथ यात्रा शुरू की। रायबरेली लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी करते हैं। यह कदम ऐसे समय में आया है, जब दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे थे। अखिलेश यादव सार्वजनिक रूप से यह कहते रहे हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कायम है।

2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने पांच लोकसभा सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस को एक सीट मिली थी।

पांच साल बाद, 2024 के चुनाव में तस्वीर काफी बदल गई। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 37 लोकसभा सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस ने छह सीटें जीतीं। दोनों पार्टियों ने मिलकर 43 सीटें जीतीं, जिससे राज्य में इंडिया गठबंधन, भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन से आगे रहा। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम ने एनडीटीवी से कहा कि इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगा।

जब अखिलेश यादव ने रायबरेली से अपनी रथ यात्रा शुरू की, तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने प्रतिक्रिया दी कि उनकी पार्टी मैनपुरी और इटावा से अपना अभियान शुरू कर सकती है। ज्ञातव्य है कि ये दोनों क्षेत्र समाजवादी पार्टी से मजबूती से जुड़े हुए हैं।

इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस जहां से चाहे, अपना अभियान शुरू कर सकती है, लेकिन उसे इटावा और मैनपुरी में वोट नहीं मिलेंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में अपना अभियान जारी रखेगी और उन्होंने उन बयानों को खारिज किया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को आसानी से किनारे किया जा सकता है। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी के बिना कोई कुछ नहीं"। उन्होंने आगे कहा, "किसी गलतफहमी में मत रहिए, आपने देखा, बंगाल में क्या हुआ।"

समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जवाब में जोर देकर कहा है कि अंतिम फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। पार्टी सांसद जिया उर रहमान बर्क़ ने कहा कि पार्टी ने मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों से लेकर चुनाव में कथित अनियमितताओं तक के मुद्दे "सड़क से लेकर विधानसभा तक" उठाए हैं।

लेकिन उन्होंने कहा कि गठबंधन कब बनेगा और सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इसका फैसला अखिलेश यादव करेंगे, जबकि कांग्रेस की ओर से यह फैसला राहुल गांधी करेंगे।

उज्जैन में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस बीच, उज्जैन शहर के काजी खलीलुर रहमान ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और बाजारों में अनावश्यक रूप से न जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मस्जिद से जुड़ा मामला सुलझा लिया गया है। उज्जैन के जिलाधिकारी रौशन कुमार ने भी लोगों से गलत जानकारी पर विश्वास न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित समुदाय के लोग खुद ही धार्मिक स्थल को दूसरी जगह ले जा रहे हैं।

उपराष्ट्रपति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्वतंत्रता आंदोलन में नई ऊर्जा का संचार किया। देश के सम्मान के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने की उनकी भावना भारत के युवाओं के साहस और संकल्प का प्रतीक है।

भाजपा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जैसे मुद्दों पर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया जाएगा। सोशल मीडिया के जरिए संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने, स्थानीय प्रभावशाली लोगों और राज्य व जिला स्तर पर तेजी से प्रतिक्रिया देने वाली व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा, ताकि महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में विपक्ष को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़े। पार्टी सूत्रों के अनुसार, जमीनी स्तर की तैयारियों में बूथ समितियों को मजबूत करना, सदस्यता अभियान को विस्तार देना, कार्यकर्ताओं का नियमित प्रशिक्षण और राज्य इकाइयों तथा केन्द्रीय प्रभारियों के बीच बेहतर तालमेल शामिल होगा। नया प्रभारी ढांचा, लगातार निगरानी, फीडबैक और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, ताकि केवल तात्कालिक चुनावी अभियानों से आगे बढ़कर, संगठन की मजबूत और स्थाई मौजूदगी बनाई जा सके। कुल मिलाकर, यह बैठक संकेत देती है कि भाजपा अपने नए नेतृत्व के तहत, 2027 के चुनावों को संगठन के आपसी तालमेल और मजबूती की एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में देख रही है।

'कोमा में चल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हो गए थे। उन्हें जयपुर रैफर किया गया और यहां उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया। इसके चलते वह 90 फीसदी स्थाई निशक्त हो गए और तब से ही कोमा में ही चल रहे हैं। उनका इलाज घर पर ही किया जा रहा है। इसके बावजूद जुलाई, 2025 से उसके पति को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा। जिस कारण पूरा परिवार ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है।

नाहरगढ़ जैविक उद्यान में जन्मे बाघ शावक का वजन 13 किलो हुआ

गत 18 अप्रेल को जन्मे शावक को नियोनेटल केयर यूनिट में 24 घंटे निगरानी में रखा गया था

जयपुर, 28 सितम्बर। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में बाघिन "भक्ति" ने 18 अप्रैल को जिस बाघ शावक को जन्म दिया था, उसकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। शावक वर्तमान में स्वस्थ है और उसका व्यवहार एवं गतिविधियां सामान्य हैं। वन्यजीव चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों की टीम उसकी 24 घंटे निगरानी कर रही है। नियोनेटल केयर यूनिट में विशेष देखभाल और "हैंड रियरिंग" के कारण शावक का वजन बढ़कर 13 किलो हो गया है।

उप वन संरक्षक, वन्यजीव चिड़ियाघर डॉ. आशीष व्यास ने बताया कि बाघिन भक्ति को वर्ष 2024 में वन्यजीव एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत पुणे ज़ू से नाहरगढ़ जैविक उद्यान लाया गया था। वहाँ वर्ष 2024 में नागपुर चिड़ियाघर से लाये गए बाघ "गुलाब" को भक्ति के साथ रखा गया था।

■ अधिकारियों के अनुसार, बाघिन भक्ति के असमान्य व्यवहार तथा उसके द्वारा शावक को दूध नहीं पिलाने के कारण शावक की नाज़ुक स्थिति को देखते हुए उसे वन्यजीव चिकित्सालय की नियोनेटल केयर यूनिट में स्थानांतरित किया गया था।

अधिकारियों के अनुसार, बाघिन भक्ति के असामान्य व्यवहार और दूध नहीं पिलाने के कारण शावक की नाजुक स्थिति को देखते हुए, उसे वन्यजीव चिकित्सालय की नियोनेटल केयर यूनिट में स्थानांतरित किया गया था। यहां शावक की 24 घंटे गहन चिकित्सा निगरानी के साथ हैंड रियरिंग की जा रही है।

नियोनेटल केयर यूनिट में रखे जाने के बाद से शावक के वजन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। उसके विभिन्न चिकित्सा परीक्षण भी कराए गए, जिनकी रिपोर्ट सामान्य आई है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान के उपनिदेशक डॉ. अरविंद माथुर ने बताया कि शावक को आवश्यक विटामिन, मिनरल्स और अन्य सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं। विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए उसका टीकाकरण और डिवर्मिंग भी पूरा कराया जा चुका है।

शावक की दैनिक गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार नजर रखी जा रही है। फिलहाल शावक को चिकन और चिकन सूप दिया जा रहा है। नियोनेटल केयर यूनिट में उसके लिए प्राकृतिक वातावरण तैयार किया गया है, ताकि उसे सुरक्षित और अनुकूल माहौल मिल सके। वन्यजीव चिकित्सक और विशेषज्ञ उसके स्वास्थ्य एवं विकास की नियमित निगरानी कर रहे हैं।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालौर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424, हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908